मध्यप्रदेश बजट

2019-20

सामाजिक क्षेत्र का एक विश्लेषण

VIKAS SAMVAD

विकास संवाद, ई 7—226, धन्वंतरी कॉम्प्लेक्स के सामने, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

चुनौतियों में नयी सरकार, नयी उम्मीदों का बजट

आम चुनाव के बाद मध्यप्रदेश का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई 2019 को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में मध्यप्रदेश सरकार के समक्ष चुनौती थी कि वह कैसे पिछली सरकार से बेहतर बजट प्रस्तुत कर सके और अपना जनपक्षधर चेहरा प्रस्तुत कर सके, वहीं यह भी बताना था कि केन्द्र में चूंकि अब भाजपा की सरकार है तो उसके हिस्सों में कटौती कर दी गई।

इन्हीं चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री तरूण भनौत ने वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए 214085 करोड़ के बजट अनुमान की घोषणा की है। याद रखा जाना चाहिए कि 2018-19 के लिए संशोधित बजट अनुमान 180279.2 करोड़ रूपए था। इस तरह से इस वर्ष राज्य के लिए कुल बजट 2018-19 के संशोधित अनुमानों से 18.75% की वृद्धि दर्शाता है।

एक मोटे विश्लेषण के मुताबिक 2019-20 के लिए सामाजिक क्षेत्र (राजस्व और पूंजी) के बजट में 81008.75 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2018-19 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 67003.75 करोड़ से18.75% की बढोतरी दर्शाता है। इससे पहले 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र के लिए 63704.59 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किया गया था। इस तालिका में इसे देख सकते हैं।

	Revenue+ Capital				
		2017-18 ACC	2018-19 RE	2019-20-BE	% of 2019-20 BE
		In Crore	In Crore	In Crore	In Crore
1	Education,Sports,Art And Culture	24341.82	28590.86	32046.3	39.56
2	Health and Family Welfare	7448.75	7785.08	10498.66	12.96
3	Water Supply and Sanitation,	4909.04	3231.07	4019.19	4.96
4	Housing and Urban Development	14772.67	13097.96	16802.3	20.74
5	Labour and Labour Welfare	356.04	885.2	1335.54	1.65
6	Welfare SC/ST/OBC	4418.01	5111.12	5995.49	7.40
7	Social Welfare and Nutrition	6875.9	7738.14	9689.51	11.96
8	Other	582.36	564.14	621.76	0.77
	Total of Social Service	63704.59	67003.57	81008.75	100.00
	% Growth in Social Sector's Budget (YOY)		5.18	20.90	
	Total Expenditure Budget of MP	186685.2	180279.2	214085	
	% Growth in State's Total Budget		-3.43	18.75	
	% Social Sector Investment in State's Total Budget Expenditure	34.12	37.17	37.84	
	ACC= Account/Actual Expenditure,RE= Revised Estimates,BE= Budget Estimates				

राज्य के कुल बजट में सामाजिक क्षेत्र के बजट का हिस्सा 2019-20 में लगभग 37.84 प्रतिशत है, और 2017-18 में यह 34.12% से बढ़ा है। इस नजरिए से देखें तो बजट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

2019-20 में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए बजट का अनुमान राज्य के कुल में 81008.75 करोड़ खर्च का बजट रु 214085 करोड़, कुल सामाजिक क्षेत्र के बजट में, 32046 करोड़ (39.56%) शिक्षा, खेल और कला और संस्कृति की सेवाओं के लिए रखा गया है, और इस क्षेत्र को मिलता है. बजटीय आवंटन की अधिकतम राशि शिक्षा और संबद्ध गतिविधियों का बजट रहा है संशोधित अनुमानों से 12.09% की वृद्धि हुई।

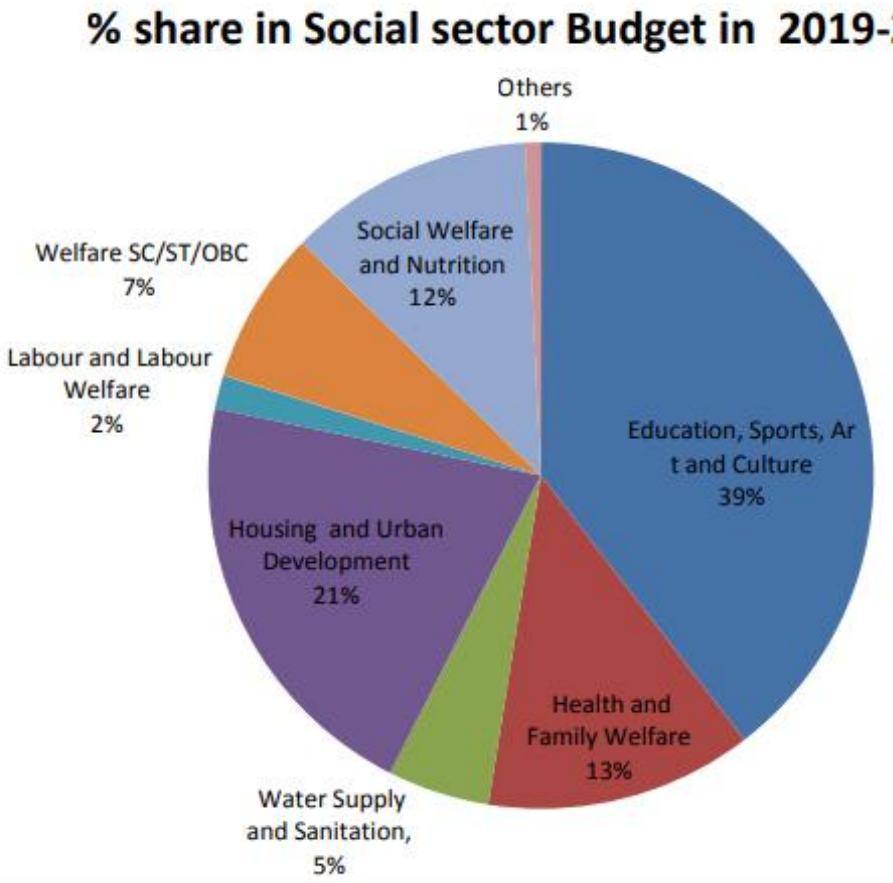

बढ़ गया मध्यप्रदेश पर कर्ज

मप्र में एक वर्ष के दौरान कर्ज 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगा। महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 तक प्रदेश पर 152745 करोड़ रुपए का कर्ज था। 31 मार्च 2019 की स्थिति में यह बढ़कर 180988 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। कर्ज पर आधारित व्यवस्था कितनी टिकाउ होती है उसे देखा जाना चाहिए। पिछली सरकार ने विकास के लिए खूब कर्ज लिया। अब कांग्रेस सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है अलबत्ता उनका कहना है कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक प्रदेश में जो भी कर्ज लिया जा रहा था वह अनुपयोगी था। उन्होंने कहा कि पिछली

कुल विनियोग राशि 233605.89 करोड़ रुपए और कुल शुद्ध व्यय 214065.02 करोड़ का प्रावधान।

राजस्व आधिक्य 732.63 करोड़ रुपए।

सकल राज्य घरेलु उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.34% अनुमानित।

अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 179353.75 करोड़ रूपए। जिसमें राज्य के सेवंय के कर की राशि 65273.74 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों से में प्रदेश का हिस्सा 63750.81 करोड़ रुपए।

करेतर राजस्व 13968.27 करोड़ रुपए एवं केंद्र से प्राप्त सहायता अमुदान 36360.93 करोड़ रुपए शामिल।

वर्ष 2019-20 में वर्ष 201819 के पुनरीक्षण अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 23.69% की वद्धि अनुमानित।

वर्ष 2019-20 में राजस्व व्यय 178621.12 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2018-10 के पुनरीक्षित अनुमान से 151022.46 करोड़ से 18,27% अधिक अनुमानित।

वर्ष 2018-19 में पूंजीगत परिव्यय 29256.78 करौड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 35463.90 करोड़, 21.22% की वृद्धि अनुमानित।

पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.68% अनुमानित।

सकल घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का प्रतिशत 0.08%

सरकार कहती थी कि हमने बीमारू राज्य को दुरुस्त किया, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम गरीबी में नीचे से तीसरे स्थान पर हैं। 15 वर्ष में उन्होंने कर्ज लिया, जो मर्ज बना रहा। हम नियमानुसार ही कर्ज ले रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास ध्यान

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे बहुत महत्वपूर्ण मानव विकास क्षेत्रों के लिए बजट रुपये के साथ निर्धारित किया गया था। राज्य के कुल बजट में 12.96% की प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 10498.66 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को प्राथमिकता दी गई है और 2018-19 के संशोधित अनुमान से 2019-20 में बजट परिव्यय में 34.86% की वृद्धि की गई है।

यह अच्छी बात है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया और न केवल आधारभूत सुविधाओं बल्कि मानव संसाधनों के नजरिए से भी प्रावधानों को ध्यान में रखा है। अब जरूरत इस बात की है कि इन प्रावधानों को बजट घोषणाओं के अनुसार लागू भी किया जाए। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति बहुत लचर है। जनसंख्या के नजरिए से देखा जाए तो प्रदेश में 2229 स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है। देश में लगभग डॉक्टर से जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं की कमी है। मध्यप्रदेश में भी तकरीबन छह हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तुरंत आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने इन परिस्थितियों केा देखते हुए राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने की घोषणा की है। इसका मतलब होगा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से सुनिश्चित कराएगी और इलाज पाना लोगों का अधिकार होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

सरकार ने इसके लिए प्रदेश में छह नए सिविल अस्पताल, सत्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 329 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 308 नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही तीन नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, इस मेडिकल कॉलेजों के

जरिए प्रदेश में 850 नई सीट बढ़ेंगी। पीजी की भी 203 सीटें बढ़ेंगी। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों को भी बढ़ाया जाना उतना ही जरूरी है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नजरिए से प्रदेश में 1065 पदों पर एवं 525 एमबीबीएस डॉक्टरों की पदस्थापना की जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों के लिए दस हजार 472 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

छह नए सिविल अस्पताल स्थापित करने की योजना

प्रदेश में छह नए सिविल अस्पताल, 70 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 329 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 308 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने और वर्तमान कॉलेजों में सीट वृद्धि के साथ कुल 850 सीटों की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 10472 करोड़ का प्रावधान है।

कुपोषण दूर करना प्राथमिकता बनेगा: मध्यप्रदेश में कुपोषण सबसे बड़ा कलंक रहा है।पिछले शासनकाल में भी इस पर बहुत काम हुआ पर जिस गति से यह घटना चाहिए उस गति से नहीं हो पा रहा है। अब कमलनाथ सरकार ने इस पर एक बार फिर नए सिरे से मंथन करना शुरू किया है। इसके लिए बजट में समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन की बात कही गई है। इसके साथ ही नौ जिलों में कुपोषण दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने की बात की गई है।

किसान कर्ज माफी का सवाल

कर्जमाफी किसानों की बड़ी उम्मीर रही है। राहुल गांधी की घोषणा कि सरकार बनने के दस दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, से किसानों को लग रहा था कि सचमुच ऐसा होगा, लेकिन प्रक्रियागत कारणों से सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं हो पाए। इसे विपक्ष ने खासा मुद्दा बनाया और सरकार की इस पर किरकिरी होती रही। आचार संहिता लागू करने से सरकार यह नहीं कर पाई और कर्जमाफी की प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा। अब प्रस्तुत बजट में वित्तमंत्री ने बताया है कि अब तक उनकी सरकार ने 20 लाख किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। तकरीबन सात हजार करोड़ रूपए का कर्ज माफ किया गया है। अब दूसरे चरण में किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों में उम्मीद जागेगी।

किसानों के नजरिए से एक अच्छी घोषणा यह है कि मछुआरों और पशुपालकों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। इससे प्रदेश में पशुपालन और मछलीपालन को बढ़ावा मिलेगा। यह सरकार का एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। एक हजार गोशालाओं के लिए अभी 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोशालाओं के लिए तीन तरह के मॉडल पर काम कर रहे हैं। स्वयं सेवी संगठनों की गोशालाओं के लिए प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपए देने का निर्णय लिया है।

किसान सलाहकार परिषद के गठन का ऐलान किया गया, जो किसानों के साथ संवाद का उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। बजट में किसानों को कमलनाथ सरकार ने सौगात देते हुए कृषि योजनाओं को लिए 22 हजार 736 करोड़ का बजट आवंटन किया, जो कि पिछले साल से 145 फीसदी अधिक था। इसके साथ किसानों की कर्जमाफी के लिए 8 हजार करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया। इसके साथ किसान सलाहकार परिषद के गठन का ऐलान किया गया, जो किसानों के साथ संवाद का उनकी परेशानियों को दूर करने का काम करेगी।

इसके साथ ही बजट में कृषक बंधु योजना के शुरू करने का भी ऐलान किया गया जिसमें गांव में किसानों को चयनित कर उन्हें उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही सहकारी बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए 1 हजार करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। सरकार ने बजट में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू करने का ऐलान किया।

स्वच्छता और जलापूर्ति का बजट बढ़ाया

2019-20 के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए बजट परिव्यय 4019.19 करोड़ रुपये है। यह पिछले वर्ष से 24.39% की वृद्धि दर्ज की है, लेकिन राज्य के सामाजिक क्षेत्र के बजट में जल आपूर्ति और स्वच्छता का हिस्सा केवल 4.96% है। बजट प्रस्ताव में ग्रामीण पेयजल के लिये 4036 करोड़ का प्रावधान भी स्वागतेय है।

ऐसा लगता है कि मप्र राज्य की बजट योजना में आवास और शहरी विकास को अधिक प्राथमिकता मिल रही है, क्योंकि 2019-20 में सामाजिक क्षेत्र के विकास में इस क्षेत्र का बजट हिस्सा 20.74% है। इस क्षेत्र के लिए बजट 2019-20 में 13097.96 (2018-19-RE) करोड़ से बढ़ाकर 16802.3 करोड़ कर दिया गया है। इस क्षेत्र में बजट परिव्यय में प्रतिशत वृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि (28.28%) है।

श्रम कल्याण के लिए निर्धारित बजट आरएस है। 1335.54 और इस क्षेत्र के बजट का हिस्सा सामाजिक क्षेत्र के बजट में सिर्फ 1.65% है। बेशक, 2018-19 के संशोधित अनुमानों से श्रम कल्याण बजट में 50% की वृद्धि की गई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों जैसे सामाजिक रूप से हाशिए के समूहों के सामाजिक कल्याण के लिए बजट बढ़ाकर रु। 2019-20 में 5995 करोड़ और संशोधित अनुमान से 7.40% की वृद्धि दर्ज की गई है।

राज्य के सामाजिक क्षेत्र के विकास बजट में सामाजिक कल्याण और पोषण बजट का हिस्सा 11.96% है। सामाजिक कल्याण और पोषण के लिए बजट रुपये से बढ़ा दिया गया है। 7738.14 करोड़ (2018-19- आरई) से रु। 2019-20 में 9689.51 करोड़। सामाजिक कल्याण और के लिए बजट 25.22% बढ़ोतरी के साथ पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इस प्रकार एमपी राज्य के सामाजिक क्षेत्रों के लिए बजट रुपये के साथ निर्धारित किया गया है। 2019-20 के लिए 81008.75 करोड़ और रुपये से बढ़ा दिया गया है। 67003.57 करोड़ (2018-19-आरई)।

सामाजिक सेक्टर के बड़े ऐलान : बजट में सरकार ने बुजर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर दोगुना करते हुए 600 रुपए किए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही बजट में प्रदेश में आदिवासियों के संस्कृति के संरक्षण और उनके उन्नयन के लिए आष्ठान योजना शुरू करने का ऐलान किया है।

लाड़ली लक्ष्मी और कन्या विवाह योजना बजट बढ़ा

लाड़ली लक्ष्मी योजना में वर्ष 2018-19 में 752 करोड़ रुपए का खर्च आया। वर्तमान बजट में इसके लिए करीब 922 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह पिछली सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना में भारी भरकम वृद्धि हुई है। इसका बजट 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।